Ref. No.: 1172 **Date: 28.08.2023**

To
Add. Principal Chief Conservator of Forest cum
Nodal Officer, FCA,
Aranya Bhawan,
Jhalana Institutional Area
Jaipur

Subject: Diversion of 3.9133 ha of Forest Land for Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/Others/146292/2021.

Reference: Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Integrated Regional Office (IRO), Jaipur (Rajasthan)

Dear Sir,

With reference to above mentioned subject, we would like to inform you that, we have submitted the complete compliance of the Stage-I approval but after examinational of the said compliance by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Integrated Regional Office (IRO), Jaipur (Rajasthan) some EDS has been raised therefore, we are herewith submitting the point wise compliance report for your reference and necessary action please.

Sr. No.	EDS Raised by MoEF&CC	Point wise Compliance
1-	The User Agency has not submitted/attached the proceedings of DLC, SDLC & Gram Sabha Resolution, Thus, Certificate of Collector under FRA, 2006 shall be submitted in proper format along with all the enclosures i.e. proceedings of DLC, SDLC & Gram Sabha Resolution.	We hereby undertake that complete compliance of the FRA, 2006 has been completed and enclosed with Stage-I Compliance report. Again, we are herewith submitting the Copy of FRA Certificate along with annexures/proceedings.
2-	Non-forest land of CA shall be notified as RF/PF under relevant rules and copy at the notification shall be submitted to this office.	We hereby undertake that, equal non forest land has been muted and hand over to State Forest department. Role of user agency has been completed and Non-forest land of CA shall be notified as RF/PF by State Government.

You's faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer - West
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Copy for your reference and necessary action please:

1. Dy. Conservator of Forest, wildlife, Jodhpur.

Annexure-I

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JODHPUR

*****

No. 383 Dated. 06/02/2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that a total area **3.9133 hectare** of forest land from **Gram Genva** is proposed to be diverted in favour of **Jodhpur Development Authority, Jodhpur.** Gram Genva, Tehsil Jodhpur (purpose for diversion of forest land) for Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of Approach Road from Kaylana Main Road of Machia Fort comes under the jurisdiction of Gram Genva, Jodhpur, Ward No. 01 and 68 of Nagar Nigam Jodhpur(South).

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.9133 hectare** of forest area proposed from Gram Genva Ward No. 01 and 68 of Nagar Nigam Jodhpur(South) for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s)(**N/A**), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure B to Annexure C.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent on it. (**N/A**)

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.

(Himanshu Gupta)
District Collector
Jodhpur
Date : 06/02/2023

जिला कलक्टर जोधपुर

No. Revenue/Forest/Diversion/23/384-385
Copy Forwarded to :
1. DCF, Teritorial, Jodhpur.
2. Secretary, Jodhpur Development Authority, Jodhpur(Raj.)

District Collector
Jodhpur

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर
www.jodhpur.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– राजस्व/FRA/2023/382 दिनांक : 06/02/2023

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा माचिया फोर्ट के पुनरूद्धार एवं माचिया बायोलॉजिकल पार्क से राष्ट्रीय राजमार्ग वाया माचिया फोर्ट सड़क निर्माण हेतु कायलाना झील के समीप ग्राम गेंवा, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820 एवं 822 रकबा 3.9133 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त के संबंध में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) के पत्र क्रमांक प.6 (14) प्रसु/अनु–3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6)3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्त्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 संशोधित नियम 2012 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.02.2023 को आहूत की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री हिमांशु गुप्ता — जिला कलक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष)
2. श्री अभिषेक सुराणा — मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर
3. श्री अजीत उचई — उप वन संरक्षक, जोधपुर

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर(उत्तर) द्वारा दिनांक 01.02.2023 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवं सड़क निर्माण किये जाने से किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उपखण्ड स्तरीय समिति ने माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवं सड़क निर्माण की अनुमोदित भूमि पर प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से पारित किया है।

उक्त भूमि पर माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवं सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 3.9133 हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है।

तद्नुसार ग्राम गेंवा, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820 एवं 822 में **3.9133 हैक्टेयर** वन भूमि पर माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवं सड़क निर्माण हेतु **3.9133 हैक्टेयर** वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

उप वन संरक्षक,
जोधपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, जोधपुर

जिला कलक्टर,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर
www.jodhpur.rajasthan.gov.in

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा माचिया फोर्ट के पुनरूद्धार एवं माचिया बायोलॉजिकल पार्क से राष्ट्रीय राजमार्ग वाया माचिया फोर्ट सड़क निर्माण हेतु कायलाना झील के समीप ग्राम गेंवा, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820 एवं 822 रकबा 3.9133 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.02.2023 को प्रातः 10:00 बजे संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुएः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	हस्ताक्षर	वि.वि.
1				
2.	Ajit uchoi	DCF, Jodhpur	[signature]	
3.	Abhishek Surana	CEO, ZP, Jodhpur	[signature]	

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

: : बैठक कार्यवाही विवरण : :

माचिया फोर्ट के पुनरूद्धार एवं माचिया बयोलॉजिकल पार्क से
राष्ट्रीय राजमार्ग वाया माचिया फोर्ट सड़क निर्माण हेतु।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिये गए निर्देशानुसार वार्ड– 01 सभा की बैठक दिनांक .... के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वार्ड सभा के उक्त प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग की 3.91[illegible] हैक्टर भूमि सार्वजनिक हितार्थ वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधान के अनुरूप हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान के अनुसार गठित एवं प्रदत अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रकिया अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02.02.2023 को आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया–

1. श्री नीरज मिश्र	अध्यक्ष एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)
2. श्री चम्पालाल जीनगर	उपायुक्त नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
3. श्री विशनाराम	उपायुक्त (पश्चिम) जोधपुर विकास प्राधिकरण
4. श्री ...Ajit uchan...	[illegible] वन संरक्षक, जोधपुर
5. श्री नारायणलाल सुथार	तहसीलदार, जोधपुर
6. श्रीमती इन्द्रा राजपुरोहित	पार्षद वार्ड संख्या –1, नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
7. श्री जगदीश नायक	पार्षद वार्ड संख्या –68, नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

वार्ड सभा बैठक .... के प्रस्ताव से वन विभाग के अधीन भूमि में से माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवम् सड़क निर्माण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया, जिसमें कायलाना झील के समीप ग्राम गेंवा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820, 822 रकबा 3.9[illegible] हैक्टर भूमि जो वन विभाग के नाम दर्ज है। उक्त भूमि माचिया किले के संरक्षण शहीद स्मारक के विकास एवम् सड़क निर्माण के उपयोग में लिये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है। सभी रिकॉर्ड देखने के पश्चात् व वर्तमान मौका स्थिति अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी काबिज नहीं हैं या अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,

Indra Rajpu

अधिशाषी अभियन्ता
जोन पश्चिम
जो. वि. प्रा. जोधपुर

2006 तथा नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार का कोई दावा लंबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवम् सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि जनहित, शहर विकास, पर्यटन, एवं सौन्दर्यकरण एवं धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से उपयोग में लिये जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया जाता है। आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावें।

(श्री नीरज मिश्र)
अध्यक्ष एवं उपखण्ड
अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

(श्री चम्पालाल जीनगर)
उपायुक्त नगर निगम,
जोधपुर (दक्षिण)

(श्री विशनाराम)
उपायुक्त (पश्चिम) जोधपुर
विकास प्राधिकरण

(श्री .....)
वन संरक्षक
जोधपुर

(श्री नारायणलाल सुथार)
तहसीलदार
जोधपुर

(श्रीमती इन्द्रा राजपुरोहित)
पार्षद वार्ड संख्या 01
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(श्री जगदीश नायक)
पार्षद वार्ड संख्या –80
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांकः– पी.ए./बैठक/2023/123 दिनांकः– 02.02.2023

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को मूल ही बैठक कार्यवाही विवरण मय उपस्थिति अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशाषी अभियन्ता
जोन पश्चिम
जो. वि. प्राधि., जोधपुर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

बैठक कार्यवाही विवरण

वार्ड नं.–1/68 नगर निगम जोधपुर, दक्षिण (वर्ष 2022–2023)

बैठक करने की दिनांक	बैठक का स्थान	पार्षद का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक में की गयी कार्यवाही	बैठक में उपस्थिति सदस्यों के हस्ताक्षर
01/02/2023		इन्द्रा राजपुरोहित जगदीश नायक	ओमप्रकाश महेन्द्र राजेश दिलीप प्रदीप कुमार मनोहर सिंह लक्ष्मण विनोद नायक लक्ष्मण मुकेश कुमार मनोज राज हेमराज विक्रम विकाश चन्द ओम प्रकाश शिवराज Ankush	आज दिनांक 01/02/2023 को वार्ड संख्या 1 व 68 की वार्ड सभा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर माचिया किला के पुनरूद्धार, संरक्षण एवम् शहीद स्मारक के विकास एवं संडक निर्माण हेतु आवंटित भूमि के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 2 की धारा (ड) परिभाषित वन अधिकारसमिति नियम 3 (1) व 3 (2) में निहित प्रावधानों के तहत इस बैठक का आयोजन कर माचिया किले के पुनरूद्धार संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास एवं सडक निर्माण कार्य ग्राम गेवा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820 एवं 822 में 3.9133 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। उक्त भूमि को माचिया किला के पुनरूद्धार संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास एवं सडक निर्माण कार्य के उपयोग में लिये जाने हेतु अनापति प्रदान की जाती है। सभी रिकॉर्ड देखने के पश्चात व वर्तमान मौका स्थिति अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन वासी काबिज नहीं है। या अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वनअधिकारों की	9928533722 9636931177 मनोहर सिंह 9981721401 लक्ष्मण 9610890032 विनोद नायक 9511504472 लक्ष्मण 8094296425 9057530148 9352943... 8302601104 8209507... विकाश चन्द 99285... ओमप्रकाश 7878589... 9829169... Ankush 87418...

अधिशाषी अभियन्ता।
जोन-पश्चिम
... जोधपुर

				मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं हैं। अतः माचिया किला के पुनरूद्धार संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास एवं सडक निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि जनहित, शहर विकास एवं सौन्दर्यकरण की दृष्ठि से उपयोग में लिए जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया जाता हैं आवश्यक अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जायें।	

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम
जो. वि. प्राधि., जोधपुर

श्रीमती इन्द्रा राजपुरोहित
पार्षद, वार्ड नं. 1
जोधपुर नगर निगम दक्षिण

जगदीश नायक
पार्षद, वार्ड नं. 68
नगर निगम (दक्षिण), जोधपुर
मोबाईल : 9950056369

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

To,

Deputy Conservator of forest,

Jodhpur

Subject: Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)" Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Others/146292/2021.

Reference:-Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur Letter No. 8B/RAJ051/2022-JPR (744605/2022/O/o IRO (JAIPUR) dated 05th September, 2022 and Office of the Dy. Conservator of Forest, Jodhpur letter No. एफ (120ए) एफसीए / उ.व.स.व.जी.जो./2022-23/5309 dated 13th December.2022.

Sir,

With reference above mentioned cited subject, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur has granted the stage-I clearance for above mentioned project vide Letter No. 8B/RAJ051/2022-JPR (744605/2022/O/o IRO (JAIPUR) dated 05th September, 2022, Now We are herewith submitting the point wise Compliance Report for your reference and necessary action please.

(ONLINE PROPOSAL NUMBER: - FP/RJ/Others/146292/2021)

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required has been deposited of an Amount of Rs. **11,93,000/- (Elevan lakh, Ninty Three Thousand, Rupees Only)** through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated **24th January, 2023** as per Deputy Conservator of Forest, Jodhpur demand Letter

अधिशाषी अभियन्ता
खोन पश्चिम
रा. वि. प्राधि., जोधपुर

		and approved CA Scheme with 10 years maintenance. **Payment Slip enclosed.**
2.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the **3.9133 ha** forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and **revision of NPV vide Ministry letter No.5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06.01.2022** in this regard.	Net Present Value (NPV) for the **3.9133 ha** forest area to be diverted under this proposal has been deposited of an amount **Rs. 26,22,459/- (Twenty Six Lakhs, Twenty Two Thousand, Four Hundred, Fifty Nine Rupees Only)** through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated **24th January, 2023** as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and **revision of NPV vide Ministry letters No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022** **Payment Slip is Enclosed.**
3.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	We hereby undertake that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department. **Undertaking for Making Payment of NPV as Per revised rates is Enclosed.**
4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927. Or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	We hereby undertake that, The non-forest land proposed for CA has been muted in the name of Forest Department and will be notified as RF/PF prior to Stage-II approval. **Mutation copy is enclosed.**

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम
रा. वि. प्राधि., जोधपुर

5.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	We hereby undertake that, complete compliance of the FRA has been completed. **(Copy enclosed).**
6.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Division Forest Officer.	We hereby undertake that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Division Forest Officer. **Undertaking is Enclosed.**
7.	**The user agency must construct pucca wall/ chain link fencing on both side of the proposed road, with adequate height as per site requirement and conditions for protection of existing flora and fauna as well as security of tourists, as per recommendations of concerned DCF.**	**We hereby undertake that, The user agency will construct pucca wall/ chain link fencing on both side of the proposed road, with adequate height as per site requirement and conditions for protection of existing flora and fauna as well as security of tourists, as per recommendations of concerned DCF.** **Undertaking is Enclosed.**
8.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	We hereby Undertakes that, The KML file of the area to be diverted and the CA areas will be uploaded on the e-Green watch portal by Forest Department.
9.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	We hereby undertake that, all the Funds have been deposited by user agency in CAMPA fund only through e-portal **(https://parivesh.nic.in/).**

B: Conditions which needs to be strictly complied in field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	We herby undertake that, Legal status of the Forest land will be remain unchanged. **Undertaking Enclosed.**
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	We herby undertake that, Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency. **Undertaking Enclosed.**

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम
भा. वि. प्राधि., जोधपुर

3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.9133 ha Degraded Forest land (DFL), Village – Rawra, Tehsil-Baap, Range-Baap, District – Jodhpur of Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.	We hereby undertake that, Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.9133 ha Degraded Forest land (DFL), Village – Rawra, Tehsil-Baap, Range-Baap, District – Jodhpur of Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species will be planted and mono-culture of any species will be avoided. **Undertaking enclosed.**
4.	User agency shall restrict the felling of trees to 610 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the tress shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of tress shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	We hereby undertake that, User Agency will restrict the felling of trees to 610 trees/minimum number in the diverted forest land and the tree will be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of trees has been deposited by the User Agency in favour of Deputy Conservator of Forest, Jodhpur.
5.	The User Agency shall raise strip plantation on both sides of the road as per the IRC Norms.	We hereby Undertakes that, User Agency will raise strip plantation on both sides of the road as per the IRC Norms. **Undertaking Enclosed.**
6.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	We Hereby Undertakes that, speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas. **Undertaking Enclosed.**
7.	The trees with bird nests, reptiles and habitat of Wildlife was observed than such tree shall be treated with special care for relocation in the forest land by Forest Department at the cost of User Agency.	We hereby Undertake that, The trees with bird nests, reptiles and habitat of Wildlife was observed than such tree will be treated with special care for relocation in the forest land by Forest Department at the cost of User Agency. **Undertaking Enclosed.**
8.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	We hereby Undertake that, No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. **Undertaking Enclosed.**
9.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	We hereby Undertake that, layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government. **Undertaking Enclosed.**

अधिशाषी अभियन्ता
जोध-पश्चिम
रा. वि. प्राधि., जोधपुर

10.	No labour camp shall be established on the forest land.	We hereby Undertake that, No labour camp will be established on the forest land. **Undertaking Enclosed.**
11.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	We hereby Undertaking that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. **Undertaking Enclosed.**
12.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	We hereby Undertakes that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. **Undertaking Enclosed.**
13.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials under for execution of the project work.	We hereby Undertakes that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials under for execution of the project work. **Undertaking Enclosed.**
14.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	We hereby Undertakes that, The period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. **Undertaking Enclosed.**
15.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	We hereby Undertakes that, The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. **Undertaking Enclosed.**
16.	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	We hereby Undertakes that, The Forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. **Undertaking Enclosed.**
17.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	We hereby Undertakes that, User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.

अधिशाषी अभियन्ता
क्षेत्र पश्चिम
[illegible] जोधपुर

		Undertaking Enclosed.
18.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	We hereby Undertakes that, User Agency will comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project. **Undertaking Enclosed.**
19.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	We hereby Undertakes that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018. **Undertaking Enclosed.**
20.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	We hereby Undertakes that, User Agency will accept Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate form time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. **Undertaking Enclosed.**
21.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	We hereby Undertakes that, Compliance report has been uploaded on e-Portal (https://parivesh.nic.in) **Undertaking enclosed.**

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

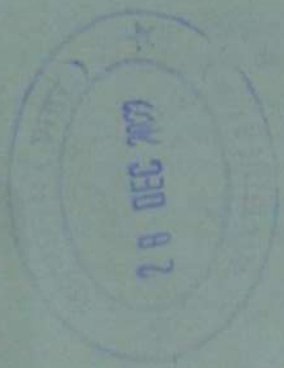

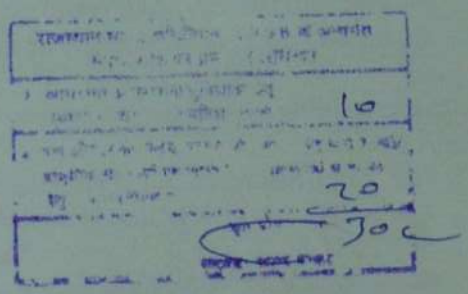

SPECIAL ADHESIVE

5288

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

Undertaking

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer (West) Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that,

1. I am an Indian Citizen.
2. I am Authorized Signatory of Jodhpur Development Authority, Jodhpur.
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee,

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम
जो. वि. प्रा., जोधपुर

shall be charged by the State Government form the User Agency. The Agency will furnish an undertaking to this effect.

4.The non-forest land proposed for CA will be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927. or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.

5. The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Division Forest Officer.

6. The user agency will construct pucca wall/ chain link fencing on both side of the proposed road, with adequate height as per site requirement and conditions for protection of existing flora and fauna as well as security of tourists, as per recommendations of concerned DCF.

7. The KML file of the area to be diverted and the CA areas will be uploaded on the e-Green watch portal by Forest Department before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

8. All the Funds have been deposited by user agency in CAMPA fund only through e-portal **(https://parivesh.nic.in/)**.

9. Legal status of the Forest land will be remain unchanged.

10. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.

11. Compensatory afforestation will be taken up by the Forest Department over 1.9722 ha Degraded forest land (DFL) at Village- Rawra, Tehsil-Baap Range-Baap, District –Jodhpur of Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species will be planted and mono-culture of any species will be avoided.

12. User Agency will restrict the felling of trees to 610 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the tree will be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees will be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

13.The User Agency will raise strip plantation on both sides of the road as per the IRC Norms.

14. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.

15. The trees with bird nests, reptiles and habitat of Wildlife was observed than such tree will be treated with special care for relocation in the forest land by Forest Department at the cost of User Agency.

16. No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused.

17. The Layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government.

18. No labour camp will be established on the forest land.

19. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

अधिशाषी अभियन्ता
क्षेत्र-पश्चिम
रा. वि. प्राधि., जोधपुर

20. The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

21. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

22. The period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

23. The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

24. The forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

25.The User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.

26.The User Agency will comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT (s) Pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

27. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

28. User Agency will accept Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate form time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

29. Compliance report has been uploaded on e-Portal (https://parivesh.nic.in)

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A – 3

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Delvelopment Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A – 4

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, The non-forest land proposed for CA has been muted in the name of Forest Department and will be notified as RF/PF prior to Stage-II approval.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Delvelopment Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A – 6

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Division Forest Officer.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A – 7

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, The user agency will construct pucca wall/ chain link fencing on both side of the proposed road, with adequate height as per site requirement and conditions for protection of existing flora and fauna as well as security of tourists, as per recommendations of concerned DCF.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A – 8

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, The KML file of the area to be diverted and the CA areas will be uploaded on the e-Green watch portal by forest department with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A – 9

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, all the Funds have been deposited by us in CAMPA fund only through e-portal **(https://parivesh.nic.in/)**.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 1

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, Legal status of the Forest land will be remain unchanged.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 2

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 3

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, Compensatory afforestation will be taken up by the Forest Department over 3.9133 ha Degraded forest land, Village- Rawra, Tehsil–Baap, Range-Baap,District – Jodhpur, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species will be planted and mono-culture of any species will be avoided..

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 4

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency will restrict the felling of trees to 610 trees/minimum number in the diverted forest land and the tree will be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 5

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency will raise strip plantation on both sides of the road as per the IRC Norms.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 6

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, Speed regulating signage will be erected along the road at regular interviews in the Protected Areas/ Forest Areas..

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021

Date: 24/01/2023

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 7

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, The trees with bird nests, reptiles and habitat of Wildlife was observed than such tree will be treated with special care for relocation in the forest land by Forest Department at the cost of User Agency.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 8

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 9

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 10

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, No labour camp will be established on the forest land.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 11

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency on the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 12

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 13

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials under for execution of the project work.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 14

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, The period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 15

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that,The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 16

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, The Forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 17

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 18

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency will comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) Pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 19

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 19

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 20

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency will accept Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate form time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

Ref.: FP/RJ/Others/146292/2021 **Date: 24/01/2023**

Project Name: - Diversion of 3.9133 Hectare Forest Land for "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. District-Jodhpur in State of Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/Others/146292/2021

Forest land Proposed for Diversion: – 3.9133 Ha.

Date of Proposal: 29.03.2022

UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B – 21

I/We Subodh Mathur, Executive Engineer, Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) is hereby undertakes that, Compliance report has been uploaded on e-Portal (https://parivesh.nic.in)

Yours Faithfully

(Subodh Mathur)
Executive Engineer
Jodhpur Development Authority
Jodhpur

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :रावरा | पटवार मण्डल :सांवरागाँव | भू.अ.नि.वृत:कानासर | तहसील:बाप | जिला:जोधपुर

नामांतरकरण का प्रकार : जमीन आरक्षण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :814 08/06/2022	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2077-2080
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	302/301	3.3764	वन विभाग		राजकीय भूमि का खाता	1	राजकीय भूमि का खाता	306/303	3.9133	गै.मु.वन विभाग	
	303/301	94.8690	गै.मु.मगरा				वन विभाग हेतु आरक्षित	307/303	90.9557	गै.मु.मगरा	
					–बदस्तूर खसरा–		–बदस्तूर खसरा–				
खाता : 1	कुल खसरे : 68	कुल क्षेत्रफल : 1479.1153			कुल काश्तकार : 0	खाता : 1	कुल काश्तकार : 0	कुल खसरे : 69		कुल क्षेत्रफल: 1479.1153	

(क)पटवारी की रिपोर्ट: कार्यालय तहसीलदार बाप आदेश क्रमांक/ दि-8/6/22 एवं जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/5290 दि- 8/6/22 की पालना मे नामा. करण भर कर पेश है

हस्ताक्षर [signature]
पटवारी का नाम [signature]
दिनांक 8/6/22

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट : आदेशानुसार अंकन सही है [signature] 8/6/22

हस्ताक्षर ....
भू.अ.निरीक्षक का नाम कानासर
दिनांक ....

(ग)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश : माननीय जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक /FRA/JDA/2022/5290 की पालना में नामा. करण स्वीकार किया जाता है

खाता : 1	कुल खसरे : 68	कुल क्षेत्रफल : 1479.1153	कुल काश्तकार : 0	खाता : 1	कुल काश्तकार : 0	कुल खसरे : 69	कुल क्षेत्रफल : 1479.1153

[signature]

हस्ताक्षर ....
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम..................
दिनांक ....

[signature] 8/6/22

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनाँक : 1 [6/8/2022 7:55:54 PM]

अधिशाषी अभियन्ता
जोन पश्चिम
जो. वि. प्राधि. जोधपुर

	राजस्थान सरकार	**NIC-BHUNAKSHA**
	खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)	दिनांक : 08/02/2023 11:49:28 AM
जिला :जोधपुर	तहसील : बाप	भू. अ. नि. क्षेत्र :कानासर
पटवारी हल्का :सांवरागाँव	ग्राम : रावरा	

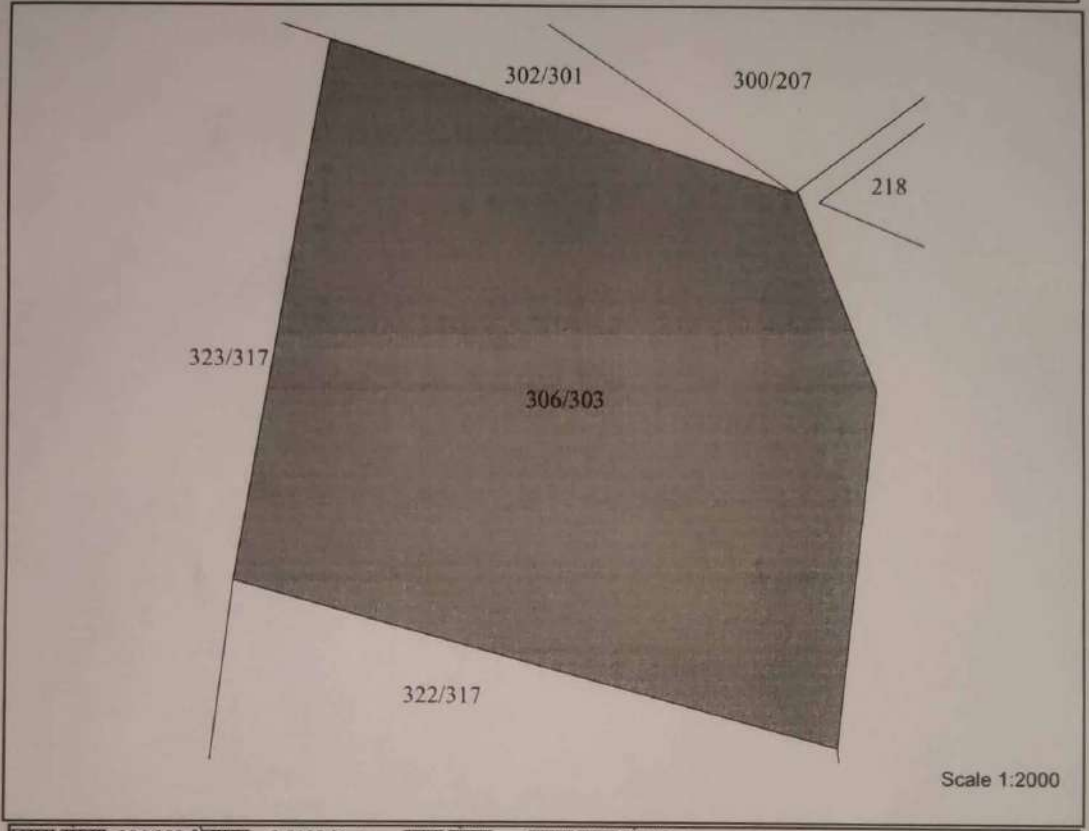

खसरा संख्या :306/303 क्षेत्रफल : 3.9133 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु.वन विभाग [3.9133]
ULPIN no : null

अधिशाषी अभियन्ता
जोन पश्चिम
सो. वि. प्रा.(द) जोधपुर

Annexure-I

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JODHPUR

*****

No. 383 Dated. 06/02/2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that a total area **3.9133 hectare** of forest land from **Gram Genva** is proposed to be diverted in favour of **Jodhpur Development Authority, Jodhpur.** Gram Genva, Tehsil Jodhpur (purpose for diversion of forest land) for Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of Approach Road from Kaylana Main Road of Machia Fort comes under the jurisdiction of Gram Genva, Jodhpur, Ward No. 01 and 68 of Nagar Nigam Jodhpur(South).

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.9133 hectare** of forest area proposed from Gram Genva Ward No. 01 and 68 of Nagar Nigam Jodhpur(South) for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s)(**N/A**), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure B to Annexure C.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent on it. (**N/A**)

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.

(Himanshu Gupta)
District Collector
Jodhpur
Date : 06/02/2023

जिला कलक्टर जोधपुर

No. Revenue/Forest/Diversion/23/384-385
Copy Forwarded to :
1. DCF, Teritorial, Jodhpur.
2. Secretary, Jodhpur Development Authority, Jodhpur(Raj.)

District Collector
Jodhpur

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर
www.jodhpur.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– राजस्व/FRA/2023/382 दिनांक : 06/02/2023

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा माचिया फोर्ट के पुनरूद्धार एवं माचिया बायोलॉजिकल पार्क से राष्ट्रीय राजमार्ग वाया माचिया फोर्ट सड़क निर्माण हेतु कायलाना झील के समीप ग्राम गेंवा, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820 एवं 822 रकबा 3.9133 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त के संबंध में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) के पत्र क्रमांक प.6 (14) प्रसु/अनु–3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6)3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्त्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 संशोधित नियम 2012 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.02.2023 को आहूत की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री हिमांशु गुप्ता — जिला कलक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष)
2. श्री अभिषेक सुराणा — मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर
3. श्री अजीत उचई — उप वन संरक्षक, जोधपुर

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर(उत्तर) द्वारा दिनांक 01.02.2023 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवं सड़क निर्माण किये जाने से किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उपखण्ड स्तरीय समिति ने माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवं सड़क निर्माण की अनुमोदित भूमि पर प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से पारित किया है।

उक्त भूमि पर माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवं सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 3.9133 हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है।

तद्नुसार ग्राम गेंवा, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820 एवं 822 में **3.9133 हैक्टेयर** वन भूमि पर माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवं सड़क निर्माण हेतु **3.9133 हैक्टेयर** वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

उप वन संरक्षक,
जोधपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, जोधपुर

जिला कलक्टर,
जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर
www.jodhpur.rajasthan.gov.in

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा माचिया फोर्ट के पुनरूद्धार एवं माचिया बायोलॉजिकल पार्क से राष्ट्रीय राजमार्ग वाया माचिया फोर्ट सड़क निर्माण हेतु कायलाना झील के समीप ग्राम गेंवा, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820 एवं 822 रकबा 3.9133 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.02.2023 को प्रातः 10:00 बजे संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुएः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	हस्ताक्षर	वि.वि.
1				
2.	Ajit uchoi	DCF, Jodhpur	[signature]	
3.	Abhishek Surana	CEO, ZP, Jodhpur	[signature]	

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

: : बैठक कार्यवाही विवरण : :

माचिया फोर्ट के पुनरूद्धार एवं माचिया बयोलॉजिकल पार्क से
राष्ट्रीय राजमार्ग वाया माचिया फोर्ट सड़क निर्माण हेतु।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिये गए निर्देशानुसार वार्ड– 01 सभा की बैठक दिनांक .... के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वार्ड सभा के उक्त प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग की 3.91[illegible] हैक्टर भूमि सार्वजनिक हितार्थ वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधान के अनुरूप हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान के अनुसार गठित एवं प्रदत अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रकिया अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02.02.2023 को आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया–

1. श्री नीरज मिश्र	अध्यक्ष एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)
2. श्री चम्पालाल जीनगर	उपायुक्त नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
3. श्री विशनाराम	उपायुक्त (पश्चिम) जोधपुर विकास प्राधिकरण
4. श्री ...Ajit uchan...	[illegible] वन संरक्षक, जोधपुर
5. श्री नारायणलाल सुथार	तहसीलदार, जोधपुर
6. श्रीमती इन्द्रा राजपुरोहित	पार्षद वार्ड संख्या –1, नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
7. श्री जगदीश नायक	पार्षद वार्ड संख्या –68, नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

वार्ड सभा बैठक .... के प्रस्ताव से वन विभाग के अधीन भूमि में से माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवम् सड़क निर्माण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया, जिसमें कायलाना झील के समीप ग्राम गेंवा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820, 822 रकबा 3.9[illegible] हैक्टर भूमि जो वन विभाग के नाम दर्ज है। उक्त भूमि माचिया किले के संरक्षण शहीद स्मारक के विकास एवम् सड़क निर्माण के उपयोग में लिये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है। सभी रिकॉर्ड देखने के पश्चात् व वर्तमान मौका स्थिति अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी काबिज नहीं हैं या अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,

अधिशाषी अभियन्ता
जोन पश्चिम
जो. वि. प्रा. जोधपुर

2006 तथा नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार का कोई दावा लंबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः माचिया किले के संरक्षण, शहीद स्मारक के विकास एवम् सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि जनहित, शहर विकास, पर्यटन, एवं सौन्दर्यकरण एवं धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से उपयोग में लिये जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया जाता है। आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावें।

(श्री नीरज मिश्र)
अध्यक्ष एवं उपखण्ड
अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

(श्री चम्पालाल जीनगर)
उपायुक्त नगर निगम,
जोधपुर (दक्षिण)

(श्री विशनाराम)
उपायुक्त (पश्चिम) जोधपुर
विकास प्राधिकरण

(श्री .....)
वन संरक्षक
जोधपुर

(श्री नारायणलाल सुथार)
तहसीलदार
जोधपुर

(श्रीमती इन्द्रा राजपुरोहित)
पार्षद वार्ड संख्या 01
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(श्री जगदीश नायक)
पार्षद वार्ड संख्या –80
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांकः– पी.ए./बैठक/2023/123 दिनांकः– 02.02.2023

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को मूल ही बैठक कार्यवाही विवरण मय उपस्थिति अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशाषी अभियन्ता
जोन पश्चिम
जो. वि. प्राधि., जोधपुर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

बैठक कार्यवाही विवरण

वार्ड नं.–1 / 68 नगर निगम जोधपुर, दक्षिण (वर्ष 2022–2023)

बैठक करने की दिनांक	बैठक का स्थान	पार्षद का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक में की गयी कार्यवाही	बैठक में उपस्थिति सदस्यों के हस्ताक्षर
01 / 02 / 2023		इन्द्रा राजपुरोहित जगदीश नायक	ओमप्रकाश महेन्द्र राजेश दिलीप प्रदीप कुमार मनोहर सिंह लक्ष्मण विनोद नायक लक्ष्मण मुकेश कुमार मनोज राज हेमराज विक्रम विकाश चन्द ओमप्रकाश शिवराज Ankush	आज दिनांक 01 / 02 / 2023 को वार्ड संख्या 1 व 68 की वार्ड सभा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर माचिया किला के पुनरूद्धार, सरंक्षण एवम् शहीद स्मारक के विकास एवं संडक निर्माण हेतु आवंटित भूमि के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 2 की धारा (ड) परिभाषित वन अधिकारसमिति नियम 3 (1) व 3 (2) में निहित प्रावधानों के तहत इस बैठक का आयोजन कर माचिया किले के पुनरूद्धार संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास एवं सडक निर्माण कार्य ग्राम गेवा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 819, 820 एवं 822 में 3.9133 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। उक्त भूमि को माचिया किला के पुनरूद्धार संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास एवं सडक निर्माण कार्य के उपयोग में लिये जाने हेतु अनापति प्रदान की जाती है। सभी रिकोर्ड देखने के पश्चात व वर्तमान मौका स्थिति अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन वासी काबिज नहीं है। या अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वनअधिकारों की	9414450276 महेन्द्र 6350002[illegible] 9828533722 9636931177 मनोहरसिंह 9981721401 लक्ष्मण 9610890032 विनोद नायक 9511504477 लक्ष्मण 8094296425 9057570148 935294327[illegible] 8302601104 820950790[illegible] विकाश चन्द 99285228[illegible] ओमप्रकाश 787858900[illegible] 984916[illegible] Ankush 874189[illegible]

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम
[illegible] जोधपुर

				मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं हैं। अतः माचिया किला के पुनरूद्धार संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास एवं सडक निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि जनहित, शहर विकास एवं सौन्दर्यकरण की दृष्ठि से उपयोग में लिए जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया जाता हैं आवश्यक अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जायें।	

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम
जो. वि. प्राधि., जोधपुर

Indra Raj P

श्रीमती इन्द्रा राजपुरोहित
पार्षद, वार्ड नं. 1
जोधपुर नगर निगम दक्षिण

जगदीश नायक
पार्षद, वार्ड नं. 68
नगर निगम (दक्षिण), जोधपुर
मोबाईल : 9950056369

150 दलित परिवारों के पट्टेशुदा भूखण्डों पर भूमाफियाओं का कब्जा

पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन सुनवाई में जयपुर जाकर गुहार लगाई है

कोटपूतली, (निसं)। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा के ग्राम खरकड़ी में एससी, एसटी वर्ग के 150 गरीब परिवारों के पट्टेशुदा भूखण्डों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने का मामला सामने आया है।

इस सम्बंध में पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन सुनवाई में जयपुर जाकर गुहार लगाई है। जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जिला कलेक्टर से मामले में रिपोर्ट भी तलब की गई है। मुख्यमंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में ग्राम खरकड़ी निवासी पीड़ित सतीश कुमार आर्य, सुभाष, शशीकांत, रविकांत, जोगेन्द्र, राजेश, मुकेश, संजय, फूलचंद समेत बड़ी संख्या में पीड़ितों ने अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत की ओर से एससी, एसटी के गरीब परिवारों को भूमि का आंवटन कर 07 नवम्बर 2019 को पट्टे जारी कर दिये गये थे।

आबादी क्षेत्र से लगती उक्त भूमि को शेरसिंह, गिरधारी, मातादीन आदि ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में भूखण्डों को मिला लिया। इस पर ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव को घटना से अवगत करवाया तो उन्होंने अपने सजातिय लोगों पर कार्यवाही करने की बजाय पट्टों को निरस्त करने की धमकी दी। जबकि समस्त पट्टे उप पंजीयक द्वारा रजिस्टर्ड भी किये गये है।

सरपंच ने अपने खास मिलने वाले लोगों के तो मकान बनवा दिये, बाकि के भूखण्डों को खेत में मिलवा दिया। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से पूर्व में 150 पट्टे एससी, एसटी परिवारों को जारी किये गये थे, जिन पर अब कब्जा कर लिया गया है। एक ओर जहां

- **पीड़ितों ने ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव को घटना से अवगत करवाया तो उन्होंने अपने सजातिय लोगों पर कार्यवाही करने की बजाय पट्टों को निरस्त करने की धमकी दी**
- **मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट**

राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर गरीब दलित परिवारों को उनके आंवटित भूखण्डों के आवासीय पट्टे देकर पुर्नवास की व्यवस्था कर रहे है। वहीं दूसरी ओर दलित परिवारों के आवासीय भूखण्डों पर दबंग कब्जा कर उनके घर को उजाड़ने पर तुले हुए हैं।

उक्त भूखण्ड ग्राम खरकड़ी के अन्तर्गत नगर परिषद कोटपूतली के अधीन आते हैं। ज्ञापन में कड़ी कानूनी कार्यवाही कर पीड़ित परिवारों को उनके भूखण्डों का कब्जा दिलवाने की मांग की गई है। पीडित परिवारों की ओर से ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, पंचायती राज सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसडीएम कोटपूतली, पंचायत समिति विकास अधिकारी व नगर परिषद कोटपूतली के आयुक्त को भी भेजी गई है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस सम्बंध में जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर अविलम्ब तथ्यात्मक टिप्पणी व रिपोर्ट भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है।

फसल खराबे का सर्वे करने अब तक नहीं पहुंचे पटवारी

कई गांवों में पटवारियों ने स्वयं न जाकर अपने अवैध सहायकों से खराबे का सर्वे करवाया है

- **आरोप है कि राजियासर, सूरतगढ़, जैतसर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला तथा सादुलशहर के कई गांवों के खेतों मे सर्वे के लिए टीमें नही पहुंची**

श्रीगंगानगर, (निसं)। पाले से फसलों के खराब होने के बाद राजस्व विभाग ने 17 जनवरी 2023 को सभी कलेक्टरों को नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश जारी किए। इसमें सभी पटवारियों को दो सप्ताह में सभी खेतों में स्वयं जाकर खराबे का आकलन करना था। अब यह खराबा रिपोर्ट फाइनल हो रही है।

लेकिन हकीकत यह है कि पटवारी व गिरदावर खेतों में अब तक पहुंचे ही नहीं। अधिकांश ने घरों में बैठकर ही खराबे का आकलन कर लिया। आरोप है कि राजियासर, सूरतगढ़ , जैतसर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला तथा सादुलशहर के कई गांवों के खेतों मे सर्वे के लिए टीमें नही पहुंची वहां किसानों का दर्द था कि 15 दिन पहले तक जहां सरसों की फसल लहलहा रही थी। वहां अब सिर्फ तबाही है।

सरकार के आदेश आने के बाद से हम पटवारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पटवारी खेतों में आए ही नहीं। किसानों ने कहा कि कृषि विभाग औसतन 12 से 25 फीसदी नुकसान का दावा कर रहा है, जबकि नुकसान 40 से 80 फीसदी तक है। किसानों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। बीमा कंपनियों का कहना है कि ओले, अतिवृष्टि या शीतलहर से फसलों में खराबा है तो 72 घंटे में हमें सूचना दें। इसके लिए टोल फ्री नंबर 18002091111 भी जारी किया गया है, लेकिन ज्यादातर समय यह नंबर ही बंद आता है।

सर्वे में हैरानी यह भी रही कि कई गांवों में पटवारियों ने स्वयं न जाकर अपने सहायकों से खराबे का सर्वे करवाया है। जबकि सरकार ने उन्हें कोई सहायक नहीं दे रखे। पटवारियों ने ये सहायक अवैध रूप से रखे हुए हैं। अनूपगढ़ से रावला के गांवों में यह शिकायतें सबसे ज्यादा मिली। किसानों ने बताया कि कई सहायक तो ऐसे भी थे, जिन्हें जमीनों व खराबे के बारे में पूरी जानकारी तक नहीं थी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दो दिन पहले विधानसभा में दावा किया कि 109.55 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जिनमें 14.92 लाख हेक्टेयर में 2 से 65 फीसदी तक खराबा हुआ है। वहीं श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो कृषि विभाग के अनुसार 1.92 लाख हेक्टेयर में औसत 12 से 25 फीसदी फसलों में नुकसान हुआ है।

सेशन खत्म होने में दो महीने शेष रहने पर आर.टी.ई. के तहत प्री प्राइमरी एडमिशन शुरू

- **प्री-प्राइमरी एडमिशन, 6 फरवरी से आवेदन**

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान के प्राइवेट स्कूल्स में अप्रैल में नया सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इन स्कूल्स में शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून के तहत प्री प्राइमरी एडमिशन के लिए अब विज्ञप्ति जारी की है। सेशन की शुरुआत में प्री प्राइमरी क्लासेज के बजाय सीधे कक्षा एक में एडमिशन दिया गया था, लेकिन सेशन 2022-23 के लिए प्री प्राइमरी एडमिशन के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है।

ऐसे में महज दो-तीन महीने के लिए ये एडमिशन हो रहे हैं, हालांकि नए सत्र से पहले अभिभावकों को अवसर मिल गया है। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि प्री प्राइमरी 3 के लिए तीन से चार वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का एडमिशन हो सकेगा। वहीं, प्री प्राइमरी 4 के लिए साढ़े तीन से पांच साल तक के बच्चों का और प्री प्राइमरी 5 के लिए साढ़े चार साल से छह साल तक के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकेगा। शिक्षा विभाग ने अब तक आवेदन की लास्ट डेट और लॉटरी की डेट्स के बारे में सूचना नहीं दी है।

जिन अभिभावकों के बच्चों का एडमिशन अब तक प्राइवेट स्कूल में नहीं हो पाया है, उन्हें आरटीई के तहत प्री प्राइमरी में अब एडमिशन मिल जाएगा। अभी नंबर नहीं आएगा तो नया सेशन भी तीन महीने में शुरू होने वाला है, तब नए सिर से एडमिशन होगा। ऐसे में दो बार अवसर मिल जाएगा। चालू सेशन में एडमिशन के लिए छह से तेरह फरवरी तक आवेदन करना होगा। इसके बाद पंद्रह फरवरी को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। अभिभावक पंद्रह से सत्रह फरवरी तक स्कूल में रिपोर्ट करना होगा। स्कूल पंद्रह फरवरी से बीस फरवरी तक ऑनलाइन मिले आवेदनों की जांच करेगा। इसके बाद अभिभावक 24 फरवरी तक करेक्शन कर सकेगा या फिर एडमिशन नियमों की पालना के बाद भी स्कूल द्वारा एडमिशन नहीं देने पर संबंधित अधिकारी को शिकायत कर सकेगा। 27 फरवरी तक आवेदन पत्रों की फिर से जांच होगी। 28 फरवरी को एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

वाहन की चपेट से पैंथर की मौत

उदयपुर, (कासं)। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा स्थित अहमदाबाद हाईवे पर शुक्रवार अल सुबह एक पेंथर की अज्ञात वाहन से कुचलने के चलते मौत हो गयी। हाइवे क्रोस करते समय किसी अज्ञात वाहन ने पैंथर को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे पैंथर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पैंथर के वाहन से कुचल जाने की सूचना पर गोवर्धन विलास पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पैंथर के शव को वन विभाग को सुपुर्द किया है। विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय में पैंथर का पोस्टमार्टम करवाने के बाद विधिवत अंतिम संस्कार किया गया।

जे.ई.ई.-मेन-2023 में दो दिन के लिए भूल सुधार का अवसर

कोटा, (निसं)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को हजारों स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। अपनी त्रुटि को सुधारते हुए एनटीए ने स्टेट कोड ऑफ इलेजिब्लिटी के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। विद्यार्थियों को स्टेट ऑफ रेजीडेंस की जगह स्टेट ऑफ इलेजिब्लिटी में करेक्शन अब 3 से 5 फरवरी शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही कैटेगिरी में करेक्शन का भी अवसर दिया गया है। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए द्वारा जेईई-मेन के लिए आवेदन के दौरान स्टेट ऑफ इलेजिब्लिटी की जगह स्टेट ऑफ रेजीडेंस पूछा गया था। इसमें स्टूडेंट्स ने उस स्टेट का नाम दिया, जिस स्टेट के वे निवासी हैं, जबकि एनटीए को इस कॉलम में उस स्टेट की डिटेल पूछनी थी, जिस स्टेट से स्टूडेंट्स ने अपनी 12वीं की परीक्षा दी है या देने वाले हैं, क्योंकि इस जानकारी के आधार पर ही स्टूडेंट्स को उस विशेष स्टेट की एनआईटी में होम स्टेट कोटे 50 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन में वरीयता दी जाती है। देश के 32 एनआईटी में करीब 26 हजार सीटें हैं, उनमें से 13 हजार सीटों पर प्रवेश होम स्टेट कोटे से दिया जाता है और शेष 13 हजार सीटों पर अदर स्टेट कोटे से एडमिशन दिया जाता है।

जोधपुर के हेरिटेज को देखने पहुंचे परदेशी पावणे

जी-20 देशों की एंप्लायमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित

जोधपुर, (कासं)। जी-20 देशों की एंप्लायमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक शुक्रवार को हुई। सुबह बैठक शुरू होने से पहले कई विदेशी प्रतिनिधियों ने जोधपुर की ब्लूसिटी जोधपुर के हैरिटेज को निहारा। शहर के घंटाघर और तुरजी का झालरा के आसपास हैरिटेज विरासत को देख डेलिगेशन अभिभूत हो गया। यहां मौजूद गाइड ने जब जोधपुर के इतिहास के बारे में बताया तो कई लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे।

जोधपुर शहर की हैरिटेज वॉक को जिला प्रशासन ने नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में तैयार किया है। नई सडक़ से लेकर घंटाघर और परकोटा शहर में विशेष तैयारी की गई। जी-20 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने जब इन को देखा तो उनका भी सकारात्मक रवैया सामने आया।

जी-20 सम्मेलन का जोधपुर सहित राजस्थान के अलग-अलग शहरों में होना यहां की टूरिज्म इकॉनामी को बढ़ाएगा। जोधपुर के हैरिटेज स्पॉट जी-20 देशों में प्रचलित होंगे। साथ ही 9 गेस्ट देश जो कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं, वहां भी जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत पहुंचेगी। ऐसे में अगले टूरिस्ट सीजन में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है।

शेखावत ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की थीमः- ऐंप्लायमेंट वर्किंग गुरप की शुक्रवार को औपचारिक शुरुआत के पहले सेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत जी-20 समूह की स्थापना के साथ से ही एक्टिव है। उन्होंने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र जोधपुर को ऐंप्लायमैंट वर्किंग ठ्ाुप की पहली मीटिंग की मेजबानी मिलना सौभाग्य की बात है। जोधपुर की अपणायत यहां आने वाले लोगों को निराश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने इस पूरे साल जी-20 मेजबानी की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी है। जिसका सही मायने में अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है और सभी समस्याओं का हल मिलकर निकालना है।

उन्होंने इसकी मैपिंग में आ रही परेशानी और इस पर ग्लोबल कैसे काम किया जा सकता है इस पर भी अपनी बात रखी। शेखावत इसके बाद मीडिया से रुबरू हुए और जी-20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया, टर्की, यूएसए, सऊदी अरब और सिंगापुर ने स्किल लेबर पर अपनी बात रखी। गिग और प्लेटफार्म इकोनॉमी पर कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया।

लगातार हो रही ऊंटों की मौत, पशुपालन विभाग बना मूकदर्शक

सिरोही के पिंडवाड़ा उपखण्ड क्षेत्र में राज्य पशु ऊंट की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा।

पिंडवाड़ा, (निसं)। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा उपखण्ड क्षेत्र के लाज शिवगढ़ गांव में राज्य पशु ऊंट की मौत का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा हैं। पिछले डेढ़ महीने में लगातार करीब पचास ऊँट मौत के शिकार हो गए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उपखण्ड प्रशासन इस पुरे मामले से अनभिज्ञ है।

पशुपालको की माने तो ऊंटो में अजीब बीमारी फैल गई है। बीमारी की चपेट में आने पर ऊंट खाना पीना छोड देता है और एक दो दिन में ही वो तड़प तड़प कर काल का ग्रास बन जाता है। पशुपालक अपनी ऊंटो को बचाने के लिए पशुपालन विभाग के डॉक्टरो से इलाज भी करवा रहे है। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय डॉक्टर इन ऊंटो का सही इलाज नहीं कर पा रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हर रोज एक दो ऊंटो की मौत हो रही है। पशुपालक बताते हैं कि पिंडवाड़ा क्षेत्र के भांवरी में नियुक्त पशु चिकित्सक डॉ. चंद्रमणि बडोली, नितोडा में कार्यरत डॉ. सुरेंद्रसिंह और आदर्श गांव में नियुक्त डॉक्टर गोवर्धन सैनी लगातार इन ऊंटो का इलाज कर रहे हैं। लेकिन ये सभी डॉक्टर इन ऊंटो की जान बचाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। इतना ही नहीं जब ये पशुपालक इन डॉक्टरो से ऊंटो के इलाज के लिए कलेक्टर के पास जाने की सलाह मांगते हैं तो ये डॉक्टर इन अनपढ़ पशुपालको को गुमराह भी कर रहे है। ये डॉक्टर इन पशुपालको से कहते हैं कि आपने ऊंटो का बीमा नहीं करवाया। इसलिए प्रशासन कुछ भी सहयोग नहीं कर सकता है। ऐसे में ना तो पशुपालक इसकी जानकारी प्रशासन को दे पा रहे हैं और ना ही ये डॉक्टर इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। जिसके कारण इतनी बड़ी पशु हानि होने के बाद भी प्रशासन पूरी तरह से बेखबर बना हुआ हैं। इस संबंध में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक बोले की निमोनिया के चलते ऊंटो की मौत हो रही है।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office, Jaipur

ए-218 & बी 216 ''अरण्य भवन'', झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004
A-218 & B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/0141-2713858, 2713786, Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

पत्र संख्या-8 बी/राज 051/2022-JPR — दिनांक-05th September, 2022

सेवा में,
शासन सचिव
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान

(Online Proposal No: FP/RJ/Others/146292/2021)

विषय-Diversion of 3.9133 ha. of forest land for Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of Approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur, Rajasthan.

संदर्भ- शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(82)वन/2022, जयपुर, दिनांक-29.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण की परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 3.9133 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 610 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृत (In-prinicipal/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA and shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated'cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the **3.9133 ha** forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04,2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 and **revision of NPV vide Ministry letter NO, 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 In this regard,**
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
4. The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PP prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.
5. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
6. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.
7. The user agency must construct pucca wall/chalo link fencing on both side of the proposed road, with adequate height as per site requirtment and conditions for protection of existing flora and fauna as well as security of tourists , as per recommendations of concerrned DCF.
8. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear project; or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
9. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final Stage-II approval:

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3 Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.9133 ha non forest land. at Village- Rawra, Tehsil -Baap, Range - Baap, Dist.-Jodhpur of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
4. User agency shall restrict the felling of trees to 610 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the user Agency with the State Forest Department,
5. The User Agency shall raise strip plantation on both sides and central varge of the road as per the IRC norms.
6. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
7. The trees with bird nests, reptiles and habitat of Wildlife was observed than such tree shall be treated with special care for relocation in the forest land by Forest Department at the cost of User Agency.
8. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
9. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
10. No labour camp shall be established on the forest land.
11. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
12. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
13. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
16. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
17. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
18. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
19. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29.01.2018.
20. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
21. The compliance report shall be uploaded on e-portal (**https://parivesh.nic.in**).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/ Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this **In-principle/Stage-I** approval shall be valid fora period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after **five (05) years**.

(श्रवण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षण / क्षेत्रीय अधिकारी

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
MAHANADI GODAWARI BASIN, RAIPUR (C.G.)

e-PROCUREMENT TENDER NOTICE

eProcurement Portal : https://eproc.cgstate.gov.in

CORRIGENDUM No.-01

In System Tender 121520/NIT No. 15/SAC/2022-23 Bemetara, Dated : 25.01.2023 Whose G-Number is 98026 dated 30.01.2023.

Following amendments are made :-

S.No.	Amendments
1.	Bid Start Date and Time : 06.02.2023, 17:31 Hours.
2.	Online Tenders are invited up to : 16.02.2023 at 17.30 Hour
3.	Bid Open Start Date and Time : 17.02.2023, 11:30 Hours.

Executive Engineer
Water Resources Division,
Bemetara (C.G.)
For, Chief Engineer
Mahanadi Godawari Basin, Raipur (C.G.)

G-98231/5

WESTERN RAILWAY - RATLAM DIVISION

TENDER NOTICE

CANCELLATION OF NIT

NO.: W/623/1/NIT Date: 27.01.2023

Tender No. RTM/2022-23/104 published in NIT No. W/623/5/1/NIT Date 27.01.2023, Name of Work: Ratlam-Chanderiya Section - Formation treatment with Biaxial Punched and oriented Geogrid and Non Woven Geo textile along with deep screening with BCM Machine. (Total = 35.16 Km), which is to be **opened** on 23.02.2023, due to unavoidable circumstances is hereby cancelled.

Divisional Rail Manager
(Western Railway)
Ratlam

AK/S/1413

Like us on facebook.com/WesternRly

NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
Ministry of Home Affairs
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi
Phone No. 011-24368800 Fax- 011-24368801
Email Id- do.nia@gov.in, info.nia@gov.in

NOTICE

Empanelment of Special Public Prosecutors for representing cases of National Investigation Agency.

National Investigation Agency intends to empanel counsels well versed with Criminal Law and Procedures to represent the State through NIA in Special Courts, High Courts and to conduct prosecution/appeals/revisions/Writ Petitions etc. on behalf of NIA in the various States and Union Territories.

2. A person empaneled shall be notified as Special Public Prosecutor under Section 15 of the NIA Act, 2008 read with Section 24(8) of Cr. P. C. by the Central Government in a State/UT for the purpose of prosecuting cases instituted by the NIA in the Special Courts and various High Courts constituted under the law. A person shall not be qualified to be appointed as a Special Public Prosecutor unless he has been in practice as an Advocate for a period of not less than ten years or has held any post, for a period of not less than ten years, under the Union of a State, requiring special knowledge of law. In nutshell, advocates having adequate experience in conducting criminal cases in Courts may only apply. The terms and conditions will be as per the guidelines fixed by Ministry of Home Affairs/Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Government of India. The applicant should apply in Proforma which may be downloaded from NIA website.

3. The duly filled application should reach NIA HQrs. at the following address on or before **30 days** from the date of this advertisement:

**Deputy Inspector General (Adm.)
National Investigation Agency HQrs.,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.**

(Santosh Rastogi, IPS)
Inspector General (Adm.)
NIA HQrs. New Delhi

CBC 19133/11/0043/2223

{ FROM PAGE 1 }

DODA CRACKS

their children safe.

"We are very much scared to stay here. We cannot even sit inside our home because the entire area has developed cracks. We seek an appropriate place to stay and provide protection to the children," said a local.

Another local there said that they have been assured of the appropriate measures to prevent any untoward incident here.

Earlier on Wednesday, a three-storey building collapsed at the Narwal Yard Transport Nagar Area of Jammu, however, the officials said that there were no casualties reported as the people were evacuated before the incident took place.

The reported incidents in the districts of Jammu are similar to the atrocities faced by the people in Joshimath town of Uttarakhand's Chamoli where severe land subsidence has sunken the holy place in the state.

Last month, hundreds of residents were shifted to relief centres in safe places after cracks appeared at several homes in Joshimath, suggesting subsidence. The reports of the widening of cracks also came to the fore after the town received heavy snowfall in January.

EXIT LETTER

across batches and programmes saying that structural safety was a trojan horse for the eradication of Louis Kahn's masterpiece.

D'Souza, who headed the top management institution for five years, will be replaced by Bharat Bhasker with effect from March 1, 2023. In the interim, the institute has appointed Prof Arindam Banerjee as the director-in-charge from February 1 to 28, 2023. HT has seen a copy of the letter, which was sent to his colleagues and alumni. The director's tenure was dogged by controversies, especially over his decision to redo the institute's logo and an initial proposal to demolish 14 student dormitories (out of 18) and reuse the land for building new structures for student residences. The move came as a surprise to many.

A section in the letter focuses on Arjuna's dilemma when he has to wage a war against his own teachers, cousins and extended family, and Krishna's advice in the Mahabharata. "It examines the choice before a decision maker confronted with the issues of the Louis Kahn complex at IIM Ahmedabad that has similar dilemma to Arjun," the letter in English read.

D'Souza wrote that the plan to raze Kahn's buildings was due to safety reasons.

"Should she (the decision maker) privilege the connections that generations have had with the poetry of light and shade that is constituted by the architecture of the Kahn designed buildings and restore, or should she be giving weight instead to the safety of the current and future users of the buildings given that the residual life of the buildings is over and reconstruct...," the letter read.

The letter concluded that theoretically, it is possible to restore or even strengthen the buildings.

In December 2020, the IIM-A governing council proposed to renovate the dorms and other buildings but a global outcry from experts and former students forced the institute to put its decision on hold. At the time, the move was opposed by several top architects, including Pritzker Prize and Padma Bhushan laureate BV Doshi, who died recently.

A decision on the final fate of the iconic buildings is pending before the IIM governing council, a senior official aware of developments said a plan was being prepared to redevelop these structures, replacing the old ones, including the dorms.

Alumni have begun protesting the decision using various social media platforms.

"IIM-A's tender in 2020 was worryingly focused on expansion of student rooms, and on facilities rather than ethos, conveying no appreciation of the role of architecture in pedagogy. The former director in his letter has appreciated the design by Kahn hence we recommend IIM-A save precious resources and get a top-class civil engineering firm to replicate or restore the world class Louis Kahn design in a structurally safe way. If that is indeed an issue," said Meenakshi Nath, an IIM-A 1987 batch student.

Prem Chandavarkar, a Bengaluru-based architectural practitioner and theorist, said, "The letter uses unnecessarily abstract philosophical arguments as a belated justification of what they had already decided to do earlier. There is no doubt that there are structural concerns including corrosion in brick-work, which needs consideration. What is also important is the value in the spirit of the original Louis Kahn campus, which uses a poetry of light and shade to construct a transcendental aura, is sacred."

In November 2022, the IIM-A governing council decided that restoration work at the heritage campus will cease altogether. While the Louis Kahn design with brick façade was to be replicated for a few of the outer dorms, the majority of the residential dorms was slated to be redeveloped based on new designs by commissioned architects.

An IIM-A official said D'Souza's term was over and that his views were personal, not reflecting the opinion of the institute. Also, D'Souza has gone on a long leave and is not reachable for comment, he added.

"A decision on the future course of action for the heritage buildings will be taken in March once the full-time director joins and the council meeting is held," he added.

MODI IN K'TAKA

and had run out of manufacturing space. India has made its mark in manufacturing a variety of helicopters, and since the requirements of the three services and the paramilitary are huge, there was a need to set up a larger facility," said Air Marshal Anil Chopra (retd), director general, Centre for Air Power Studies.

LUH will replace the army and the Indian Air Force's ageing fleets of Cheetah and Chetak helicopters. HAL expects the army and IAF to place combined orders for at least 187 light helicopters in the coming years (126 for the army and 61 for IAF).

Currently, the Cheetah and Chetak helicopters are a critical lifeline for troops in high-altitude areas, including the Siachen glacier. HAL has licence-produced 625 Cheetah and Chetak helicopters. It no longer builds them but is responsible for their maintenance and repair.

"The factory will be augmented to produce other helicopters such as LCH and IMRH. It will also be used for maintenance, repair and overhaul of LCH, LUH, advanced light helicopter (ALH) and IMRH. Potential exports of civil LUH will also be catered to from this factory," the ministry added.

The state-run plane-maker expects follow-on orders as the army and IAF have a combined projected requirement of 160 LCHs. LCH has indigenous content of 45% by value, which will progressively increase to more than 55% for the series production version, officials said.

IMRH, which will also be manufactured at Tumakuru factory, is expected to compete with Russian Mi-17 choppers in both Indian and foreign markets. HAL says the platform could have a huge market as nearly 40 air forces across the world operate Mi-17 type helicopters. The Mi-17 is the mainstay of the Indian Air Force's transport fleet.

BOTH SUSPECTS ARRESTED IN CHUNABHATTI MURDER CASE

MUMBAI: Two people, who were absconding, were arrested on Friday for allegedly stabbing a 19-year-old college student to death in Sindhi Colony, Chunabhatti, on Thursday evening. The initial probe by the Mumbai police crime branch has revealed that the victim was dating a girl, who used to be in a relationship with one of the accused.

The two arrested accused are Aditya Tribhuvan, 19, and Kalpan Sayyed, 20. The former is a resident of Deonar, whereas Sayyed is from Bhiwandi. The victim has been identified as Mudassir Shaikh, 19, a student of Vivekanand College in Sindhi Colony.

According to the police, on Thursday at around 6.30pm when Shaikh along with a girl came out of the college, Aditya and Sayyed arrived there on a scooter, stabbed Shaikh multiple times in front of the girl and fled from the scene.

Shaikh, a resident of Vashi Naka in Chembur, was rushed to the nearby hospital, where he was declared brought dead.

Meanwhile, the police were informed and teams of Chunabhatti police reached the spot and checked footages of the CCTV cameras and made inquiries. Unit 6 and 7 of the Mumbai police crime branch had also started a parallel probe in the case and their teams were also trying to trace the accused.

"The two accused had switched off their mobile phones, but based on the clues obtained by analyzing their social media activities, crime branch officials zeroed in on their location to Dharavi and nabbed them from there on Friday," said a crime branch official. Aditya's relatives stay in Dharavi, where he was hiding along with Sayyed, the police said. HTC

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/Integrated Regional Office, Jaipur

ए-218 & बी 216 ''अरण्य भवन'', झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - 302004
A-218 & B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No.: 0141-2713858, 2713786, Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

पत्र संख्या-8 बी/[illegible] 051/2022-JPR

दिनांक: 06th September, 2022

सेवा में,
शासन सचिव (वन),
शिविर सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान

(Online Proposal No: FP/RJ/Others/146292/2021)

विषय: Diversion of 3.9133 ha. of forest land for Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of Approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur, Rajasthan.

संदर्भ: शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प-1(82)वन/2022, जयपुर, दिनांक 29.07.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण की परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विचाराधीन परियोजना हेतु 3.9133 हे० वनभूमि के अपवर्तन एवं 610 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-principle/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the **3.9133 ha** forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 and **revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.**
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
4. The non-forest land proposed of CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian, Forest, Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.
5. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
6. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.
7. The user agency mast contract pucca wall/chain link fencing on both side of the proposed road, with adequate height as per site requirement and conditions for protection of existing flora and fauna as well as security of tourists, as per recommendations of concerned DCF.
8. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal will all requisite details, before issuing, working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
9. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.9133 ha non-forest land, at Village- Rawra, Tehsil - Baap, Range - Balesar, District-Jodhpur, Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
4. User agency shall restrict the felling of trees to 610 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
5. The User Agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.
6. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
7. The trees with bird nests, reptiles and habitat of Wildlife was observed than such tree shall be treated with special care for relocation in the forest land by Forest Department at the cost of User Agency.
8. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
9. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
10. No labour camp shall be established on the forest land.
11. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
12. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
13. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
16. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
17. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
18. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and NGT Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
19. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.01.2018.
20. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
21. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further it may also be noted that this **In-principle/Stage-I** approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after **five (05) years**.

[illegible]

G20

NORTHERN RAILWAY

Case No. 752-E/CMP/NRCH/2022

ENGAGEMENT OF CONTRACT MEDICAL PRACTITIONER (CMP)

Applications are invited from eligible candidates for Engagement of Contract Medical Practitioner (CMP) for ONE post in Casualty at Northern Railway, Central Hospital, Basant Lane, New Delhi. Walk in interview will be held on **13.02.2023**. Detailed advertisement with VACANCY STATUS, terms & conditions, format of application form is available on Northern Railway website **https://nr.indianrailways.gov.in** and **www.nr.railnet.gov.in/dept/personnel/pnew.html**.

MEDICAL DIRECTOR
NORTHERN RAILWAY
CENTRAL HOSPITAL
NEW DELHI

371/2023

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

Government of India
Ministry of Home Affairs
Directorate General Border Security Force
(Pers Dte — Recruitment Section)

SHORT ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF VARIOUS POSTS OF GROUP-'C' IN VETERINARY STAFF IN BSF-2023

Online applications are invited from eligible and interested Male and Female Indian citizens for filling up the under mentioned vacancies combatised (non-gazetted) posts in Group 'C' of Veterinary Staff in the Border Security Force, Ministry of Home Affairs, Government of India through online mode only for the vacancy year-2023.

Post	UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	Pay Scale
Head Constable (Veterinary)	07	02	06	03	-	18	Pay matrix Level-4 (Rs. 25,500 - 81,100/-) As per 7th CPC
Constable (Kennelman)	02	-	02	01	03	08	Pay matrix Level-3 (Rs. 21,700 - 69,100/-) As per 7th CPC

NOTE:-

(a) The applications will be accepted through online mode only.

(b) Last date for acceptance of application will be **30 days** from the date of publication of the advertisement in the Employment Newspaper.

(c) Crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of online applications.

(d) Vacancies are subject to change (may increase or decrease). BSF reserves the right to make changes or cancel or postpone the recruitment without assigning any reason.

(e) If ESM candidate not found eligible, the vacancy be filled by the respective category.

2. EDUCATIONAL QUALIFICATION/PROFESSIONAL QUALIFICATION:

(A) EDUCATION/QUALIFICATION

S/NO	POST	EDUCATIONAL QUALIFICATION
(a)	Head Constable (Veterinary)	Essential (a) 12th Class from a recognized Board; (b) Possessing minimum one year course in Veterinary Stock Assistant from any recognized Institution and having at least one year post qualification experience.
(b)	Constable (Kennelman)	Essential (a) 10th Class from a recognized Board; (b) Two year experience in handling of animals from Government Veterinary hospitals or dispensary or Veterinary College or Government Animals Farm;

Note: Candidates not in possession of requisite educational qualification/experience certificate or appearing in the examination/awaiting result need not to apply.

3. AGE: Male and female candidates between 18 to 25 years of age.

Note:- **Crucial date for determine the age limit in each case shall be closing date of receipt of online application.** However relaxation in upper age limit is available to different categories and Central Government servants as per instructions/order issued by the Central Govt. from time to time.

4. PHYSICAL STANDARD TEST (PST)

The minimum requirement for the candidates are as under :-

Measurement	Male	Female
Height	165 Cms.	150 Cms.
Chest	76 Cms (Unexpanded) 81 Cms (Expanded)	Not applicable
Weight	corresponding to Height	corresponding to Height

5. Candidates are advised to login to https://rectt.bsf.gov.in to view detailed advertisement and for submission of online application forms which will be available on BSF website after publication of advertisement in **Employment News/Rozgar Samachar.**

6. Any further information/notification in this regard will be available on the BSF Website only. Hence, candidates are advised to visit BSF website from time to time.

Dated, the 29 Jan 2023

CBC 19110/11/0108/2223

(K S Rana)
Commandant (Rectt)